categories *viz.* 'A', 'B' and 'C', keeping in view the following aspects of the films, in that order :

(1) International/National/State Awards won

(2) Thematic Value

(3) Cinematic Value

(4) Entertainment Value

(5) Year of Production

(6) No. of times the film was shown on TV and by which Kendra.

Before actual telecast, portions of the film, considered as objectionable for family viewing, are also deleted keeping in view the need for continuity of the sequences of the film.

राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के मूल्य

2861. **श्री शिव कुमार मिश्रा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश बीज तथा तराई विकास निगम द्वारा उत्पादित बीजों के मूल्यों की तुलना में राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के मूल्य अधिक होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के मूल्यों को उत्तर प्रदेश बीज तथा तराई विकास निगम के बीजों के मूल्यों के बराबर लाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम और उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा वितरित किये गये बीजों के मूल्यों के बीच अन्तर अलग-अलग फसलों के लिये भिन्न भिन्न है । 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बीजों के लिये दोनों निगमों द्वारा लिए गये खुदरा मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1983-84		1984-85	
	राष्ट्रीय बीज निगम	उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम	राष्ट्रीय बीज निगम	उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम
गेहूं	380 (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 390)	385	395	390
धान	285-315	330-355	350-380	330-355
चना	625	620	700	660
मक्का	450-550	490-620	450-550	490-570

(उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के बताये गये मूल्य अन्तः राज्य वितरण के लिए है)

इस प्रकार कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा लिए गए मूल्य राष्ट्रीय बीज निगम के मूल्यों की तुलना में कम हो सकते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम समूचे देश में किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है । निगम राज्य कृषि विभागों और अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से, अपने बिक्री काउंटरों के जरिए और अपने बीज विक्रेताओं के तंत्र के जरिए बीज का वितरण कर रहा है । राष्ट्रीय बीज निगम ने समूचे देश में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों और 84 उप-एककों की स्थापना की है और इस समय निगम के पास 2,944 विक्रेताओं का तंत्र है, जो समूचे देश में फैला हुआ है । निगम द्वारा समय पर प्राप्त किए गए सभी मांग पत्रों पर निगम के उत्पादन कार्यक्रमों में विधिवत ध्यान दिया जाता है ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अपने बीज की खरीद करता है, जबकि राष्ट्रीय बीज निगम समूचे देश में विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता है । अतः बीजों के अन्तः राज्य वितरण के लिये परिवहन की लागत, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम की लागत की तुलना में राष्ट्रीय बीज निगम के लिए अधिक है । इन दो निगमों की उत्पादन लागत के बीच इस अन्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा वसूल किये गये मूल्यों के बीच समानता का होना प्रायः संभव नहीं हो सकता है ।

तथापि, विशेष फसलों के लिये इन दो निगमों के मूल्यों के बीच अन्तर के अलग-अलग मामलों की आवश्यकतानुसार जांच की जाती है और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बिक्री मूल्यों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाता है, ताकि वे मूल्य उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों के समान हो ।

Construction of flats in pocket B-E, Janakpuri

2862. SHRIMATI USHA MALHOTRA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 387 given in the Rajya Sabha on the 3rd May, 1985 and State:

(a) whether the flats in Pocket B-E, Janakpuri have been completed and rleased for allotment in June, 1985; and

(b) if not, what are the reasons therefor and by when these are likely to be completed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) No, Sir.

(b) The flats could not be released by the traget date primarily due to labour shortage with contractor on account of poor organisation of work by him. All efforts are being made to release the flats for allotment as soon as possible.

श्रमिकों के कल्याण के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2863. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितना कितना अनुदान दिया गया और इन संस्थाओं के नाम क्या है ; और

(ख) इस संबंध में कितने संगठनों की जांच पड़ताल की गई है और ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें इस बात का दोषी पाया गया है कि जिस प्रयोजन के लिए उन्हें अनुदान मंजूर किये गये थे उनका इस्तेमाल उन्होंने उन कामों के लिए नहीं किया और फिर भी, उन्हें अनुदान दिये गये है ?